राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 306

प्रगति

समाचार पत्र

नवम्बर 2020

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास

नीति प्रयोजन और समर्थन

प्रौद्योगिकी अंतरण

शैक्षणिक कार्यक्रम

अभिनव कौशल और आजीविका

पेसा क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों में नागरिक समिति संचालित समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

3 पेसा क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों में नागरिक समिति संचालित समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

विषय-सूची

7
एनआईआरडीपीआरने मनाया संविधान दिवस, व्याख्यान और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की

8
एन आई आरडीपीआर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह

9
हैंडवाशिंग और कोविद-19 उपयुक्त व्यवहार एसबीबीसी पैकेज पर जिला और मंडल स्तर की लाइन विभागों की वर्चुअल ट्रेनिंग

10
एनआईआरडीपीआर एसएयू उत्तर प्रदेश के स्रोत व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी और एनएसएपी के सामाजिक लेखा परीक्षा पर प्रशिक्षण आयोजित

12
कोविद-19 और जोखिम संचार पर श्री सत्य साई सेवा संगठन के सेवादल का

13
सतत आवास प्रौद्योगिकियों पर आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम

14
एनआईआरडीपीआर कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध कक्षाएं आयोजित की

15
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामाजिक लेखा परीक्षा पर द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला

पेसा क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों में नागरिक समिति संचालित समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

1996 में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) (पेसा) अधिनियम लागू हुआ अनुसूचित क्षेत्रों में गाँवों / खंडो / कस्बों/ तालाबों (मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में) में एक प्रकार से रचनात्मक बदलाव लाने की उम्मीद थी। । पेसा अधिनियम का जोर आदिवासी क्षेत्रों में उनके ग्राम सभा के सुद्रदिकरण द्वारा सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रबंधन के तरीकों को पुनर्जीवित करने पर है।

1980 के दशक में, सिविल सोसाइटी द्वारा संचालित (सिविल सोसाइटी संगठन) समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (सीबीएनआरएम) का उद्भव और विस्तार हुआ था, जो गैर-सरकारी संगठनों के लिए मंच निर्धारित करता था, जिसे 'एनआरएम' समुदाय आधारित माना जाता था। इस लेख में, आदिवासी समुदायों में सीएसओ के माध्यम से सीबीएनआरएम से निकलने वाले विभिन्न विषयों को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

महाराष्ट्र में सीबीएनआरएम : अधिकारों के लिए आदिवासी संघर्ष

यह मामला आदिवासियों के उनके स्वदेशी संसाधनों के प्रबंधन के पारंपरिक अधिकार के संघर्ष की गाथा को दर्शाता है ।

समकालीन समय में, आधुनिक सीएसओ आधारित सीबीएनआरएम गतिविधियाँ एनआरएम की प्रासंगिकता को उन स्थितियों के मनोरंजन के माध्यम से पुनः स्थापित करती हैं, जिनके तहत जनजातीय समुदाय अपने संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं।

धरणी ब्लॉक के घोटा गांव में 20 हेक्टेयर में फैले जलक्षेत्र में मछली पकड़ने का प्रबंध किया गया है। वे योगदान देते हैं और मछली के बीजों का स्टॉक करते हैं और फिरतय करते है कि किस तरह से कटाई की जानी है, कभी-कभी सामूहिक रूप से कटाई, कभी-कभी एसएचजी के माध्यम से, कभी-कभी ग्रामीणों के समूह के माध्यम से अपने ग्राम सभाओं में की जाती है । एक खोज नमक एनजीओ ने उन्हें एहसास दिलाया कि यह न केवल मछली पकड़ना है, बल्कि उन्हें जल निकाय के प्रबंधन की भी जरूरत है। उन्होंने योजना बनाई और मनरेगा के तहत गाद हटाने का प्रस्ताव रखा। इसलिए, जल निकाय के गहरीकरण ने बेहतर भंडारण की अनुमति दी जिससे कृषि और मछली पकड़ने के लिए सिंचाई की सुविधा बनाए रखने में मदद मिली। इसके साथ ही, किसानों द्वारा अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए गाद का उपयोग किया जाता है। यद्दपी अपने मछली पकड़ने के प्रबंधन के माध्यम से, घोटा गांव की ग्राम सभा अपने स्वयं के सदस्यों को कोविड-19 महामारी के दौरान दूसरों की मदद के लिए इंतजार किए बिना एक छोटा सा राहत पैकेट प्रदान करने में सक्षम थी, । (स्रोत: खोज, मेलाघाट, महाराष्ट्र)

छत्तीसगढ़ में सीबीएनआरएम का अभिसरण मॉडल

यह मामला अध्ययन स्वदेशी ज्ञान और पद्धतियों का समर्थन करने के लिए बाहर से उपयुक्त तकनीकी कौशल की शुरूआत करके आदिवासी

सब्जी बेचते हुए आदिवासी (फ़ाइल इमेज) –छायांकन : डॉ. सुरजीत विक्रमण

समुदायों के विकास के लिए अग्रणी अभिसरण रणनीति पर जोर देता है।

बस्तर में, बड़े भूस्वामियों के मालिक होने के बावजूद, मारिया गोंडा का आदिवासी समुदाय अत्यंत गरीबी में जी रहा था। उपरोक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिला मनरेगा विभाग, एक सीएसओ पीआरएडीएएन के साथ, संयुक्त रूप से रेशम कीट पालन में अबतक के ग्रामीण अपलैंड्स के वैकल्पिक उपयोग को विकसित करने में लगा हुआ था।

मूल बीज और बहु गुणन केंद्र से वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के मार्गदर्शन में बस्तर ब्लॉक के आदिवासियों के लिए आदिवासियों के लिए परिचयात्मक दौरा पालन स्थल पर आयोजित की गईं। मनरेगा के तहत अर्जुना वृक्षारोपण की प्रस्तावित गतिविधि की क्षमता को समझने के बाद, समुदाय ने तीरथगढ़ परमपारा में अपने आवास के करीब 20.88 हेक्टेयर के एक उपवन स्थल की पहचान की, जिसमें उस हेमलेट से 13 मारिया गोंड घरों की निजी भूमि और निजी स्वामित्व वाली भूमि शामिल थी।

पांच एसएचजी में से एक - दंतेश्वरी स्व सहायता समुह ने नर्सरी तैयार करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने वन विभाग से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया और सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

इस तरह, उन्होंने आवश्यक मानक के 80,000 पौधे तैयार किए और उन पौधों को बेचा और रोपण के लिए एमजीएनआरईजीए को पौधे बेचकर 1,25,000 रुपये कमाए। ।

नियोजन प्रक्रिया के दौरान और उसके आसपास के क्षेत्र में जल संरक्षण संरचनाओं की आवश्यकता की पहचान की गई थी भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए, दो बरसाती झरने के बोल्डर चेक डैम, 21 हेक्टेयर के रोपण क्षेत्र में समोच्च खाइयों और ग्रामीणों द्वारा 10 परकोलेशन टैंक और खेत तालाबों का निर्माण किया गया था। इस पूरे हस्तक्षेप ने अपवाह की काफी हद तक जाँच करने और क्षेत्र को हरियाली में बदलने में बहुत प्रभावी भूमिका निभाई। । वृक्षारोपण स्थल में काम करने वाले परिवार को मजदूरी के रूप में 20,000-25,000 .रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई।

सीबीएनआरएम: झारखंड में महिला सशक्तिकरण का महत्व

यह मामला बताता है कि आदिवासी महिलाओं में उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण सहायता का आश्वासन दिया गया था ताकि वे कार्यबल की भागीदारी में पुरुषों को अवैध आसवन से दूर कर सकें।

लाक उत्पादन में महिलाओं की भूमिका परंपरागत रूप से बिखरे हुए लाक को तैयार करने और इसे बाजार में ले जाने जैसे कामों के लिए प्रतिबंधित है। इसका कारण यह है कि लाक के पेड़ लम्बे होते हैं। इसलिए, पुरुषों ने कलम लगाने और कटाई प्रक्रियाओं को अंजाम दिया है।

2013 में, गुमला में एक आदिवासी महिला , कमला ने हमारे लाक आजीविका मॉडल के हिस्से के रूप में भारतीय प्राकृतिक रेजिन और मसूड़ों के साथ पैक्स पार्टनर उद्योगिनी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाओं की एक श्रृंखला में भाग लिया। प्रशिक्षण के बाद, कमला ने बेर के पेड़ों पर कुसुमी किस्म की लाक की खेती शुरू की। वे कहती हैं, " पहले सीज़न में हमने लाक स्क्रेप बेचे और उन्हें लगभग रु. 10,000 का लाभ हुआ। इस साल हमने रु. 31,000 कमायें . " वास्तव में, अपने ज्ञान और सफलता के साथ, कमला आज अपने समुदाय में अन्य महिलाओं को उसके ही नक़्शे कदम पर चलने और एक जीवंत आजीविका के रूप में लाक कि खेती का चयन करने के लिए जुटा रही है।

कमला कैंची का उपयोग करती है कि उसे प्रशिक्षण कार्यशाला में ब्रूड लैक बंडलों - लाठी तैयार करने के समय दिया गया था - जो लाक उत्पादक कीटों से युक्त होते हैं ताकि उन्हें लाक उत्पादन के लिए तैयार किया जा सके।
(स्रोत: www.pacsindia.org)

एमपी में सीबीएनआरएम: जनजातीय समुदायों के सतत आजीविका के लिए प्रवेश द्वार

गादिया गांव का मामला अध्ययन आगे सीबीएनआरएम के माध्यम से सतत विकास और

आजीविका के वैकल्पिक स्रोत स्थापित करने के संघर्ष को दर्शाता है। इस गाँव के बैगा आदिम जनजातीय समूह के सभी 47 परिवारों को 1980 के दशक के अंत में राज्य सरकार द्वारा बांध बनाने के बाद उनकी पारंपरिक भूमि के जलमग्न होने के कारण यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। 2008 में, आठ ग्रामीणों के एक समूह ने गांव की सीमा से 0.75 मील दूर मटियारी बांध के जलाशय की जलमग्न भूमि के एक भूखंड में सब्जी की खेती शुरू की। गर्मी के मौसम के दौरान, जलाशय का जल स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे गाँव के कृषि क्षेत्रों की तुलना में मिट्टी की गुणवत्ता के साथ भूमि के एक भूखंड पर सब्जी की खेती की जाती है। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की चिंता नहीं है क्योंकि जलाशय निकट ही है ।

किसानों ने इस बहाने जैविक खाद के उपयोग का सहारा लिया कि उर्वरकों के उपयोग से जलाशय में मछलियों को संभावित रूप से नुकसान पहुंच सकता है जो उनके और पड़ोसी गांवों से संबंधित मछुआरों के लिए एक वैकल्पिक आजीविका रणनीति थी। सब्जियों का उत्पादन अप्रैल के महीने मेंमें हुआ जब सब्जियों की कीमतें बहुत अधिक होती है ताकि मुनाफा अधिकतम हो ।

इस प्रकार, भूमि के अनुपयोगी टुकड़े का उपयोग करके इस जनजातीय समूह के पोर्टफोलियो में एक वैकल्पिक आजीविका विकल्प जोड़ा गया। अपने साक्षात्कार में, आठ सदस्यीय समूह ने स्थानीय बाजार में उपज बेचने से 22,400 रुपये कमाने की सूचना दी। छह महीने की अवधि में 11,200 रुपये मूल्य की सब्जियों की खपत की ।

ओडिशा में सीबीएनआरएम के माध्यम से नीतिगत निर्णयों के बारे में जागरूकता पैदा करना

यह मामला जनजातीय समुदायों के लिए विपणन नीति को सक्षम बनाने के लिए उचित समय में बाहरी हस्तक्षेप से जागरूकता सृजन पर जोर देता है।

इमली शायद एक ऐसा गैर ईधन वन उपज है जो भारत की हर रसोई में मिलता है। हालांकि, यह एक मामूली वन उपज (एमएफपी) है और एमएफपी योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वस्तुओं की सूची में शामिल है। कंधमाल , ओडिशा के सबसे दूरस्थ जिलों में से एक है वहां स्थानीय

एक आदिवासी महिला (फ़ाइल इमेज)

व्यापारी , ईमली को परिपक्व करने और सुखाने के लिए आदिवासियों को 5 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करते है । वास्तव में, व्यापारियों ने एक ऑक्सुलर अनुमान के आधार पर एक पेड़ की सारी इमली खरीदी।

इस संदर्भ में है कि एक एनजीओ वसुंधरा ने 'एमएसपी फॉर एमएफपी' कारवां का आयोजन किया। कारवां 10 दिनों के लिए फूलबनी में गांवों के आसपास चला और वसुंधरा के कर्मचारियों ने स्थानीय भाषा में ऑडियो संदेश रिकॉर्ड किए और सार्वजनिक स्थानों पर बैठकों की योजना बनाई। उन्होंने योजनाओं के प्रावधानों की व्याख्या की और उस तक पहुँचने पर आदिवासियों को उन्मुख किया।

जब लोगों को पता चला कि इमली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 22 प्रति किलो, उन्होंने स्थानीय व्यापारियों को अपनी इमली बेचने से इनकार कर दिया। फूलबनी ब्लॉक के जाम्झरी ग्राम पंचायत में एमएफपी ने मिलकर इसे खरीदने की शुरुआत हुई। टीडीसीसी ने 22 प्रतिशत प्रति किलो की दर से दो प्रतिशत कमीशन देने के बाद इसे खरीदने का वादा किया।

अंत में, सामूहिक पंचायत के 12 गांवों में 119 परिवारों से 80 क्विंटल इमली की खरीद की गई और इसे जिला स्तर के व्यापारी को 25.50 रुपये प्रति किलो रु. में बेचा गया जो सीधे रायपुर के बड़े बाजार में बेचता है। इस साल खट्टी इमली बेचने का स्वाद वास्तव में मीठा था।

(Source: www.downtoearth.org)

ओडिशा में आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अग्रणी सीबीएनआरएम

यह मामला ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आदिवासी समुदायों के आर्थिक उत्थान को दिखाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले चिरौंजी के बीज आमतौर पर 1400 रुपये प्रति किग्रा से अधिक में उपलब्ध होती हैं। लेकिन आदिवासी और वन पर आधारित अन्य समुदाय जो बीज इकट्ठा करते हैं उन्हें वो बीज 40 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर बेचना पड़ता था।

यह लगभग चिरोंजी के बीज के लिए 120 रु का भुगतान करने के बराबर है जो बाजार मूल्य के नौ प्रतिशत से कम 1400 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की कमी और लोगों को प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी को सुनिश्चित करके वर्षों से इस तरह की कम कीमतों को बनाए रखा गया है।

चिरौंजी के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी की घोषणा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आदिवासी महिलाओं के लिए एमएसपी पर बेचने की गारंटी नहीं देता । सुंदरगढ़ में आदिवासी लोगों के साथ काम करने वाले एक सीएसओ, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट

एक आदिवासी क्षेत्र में सब्जी बाजार (फाइल इमेज) छवि क्रेडिट: डॉ. सुरजीत विक्रमण

(सीआईआरटीडी) ने एमएफपी कारवां के लिए अपने एमएसपी के प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में चिरोंजी को चुना।

जागरूकता अभियान के कारण, लोगों ने एमएसपी के बारे में पता किया और चिरौंजी के बीज को जनजातीय विकास सहकारी निगम (टीडीसीसी) को सौंपने के लिए एकत्रित किया। उन्हें बताया गया कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक स्थानीय पीपीए (टीडीसीसी के साथ पंजीकृत प्राथमिक खरीद एजेंसी) नहीं है। जैसा कि टीडीसीसी ने शुरू में अपनी उपज इकट्ठा करने से इनकार कर दिया, उन्होंने जिला कलेक्टर को याचिका दी। नतीजन, 15 दिनों में एक पीपीए का गठन किया गया था और टीडीसीसी ने अंत में 7.8 क्विंटल चिरोंजी के बीज को उठवा लिया था। संग्रहंकर्ताओं ने लगभग रु. 31,200 स्थानीय बाजार में अंततः उन्हें रु. 78,000 - रुपये प्राप्त हुए और 46,800 वृद्धिशील लाभ प्राप्त हुआ (जो उन्हें अन्यथा मिला होगा, उससे 150 प्रतिशत अधिक)।

हिमाचल प्रदेश में आदिवासी महिलाओं का सीबीएनआरएम और नृवंशविज्ञान संबंधी स्वदेशी ज्ञान

यह मामला इकोफेमिनिस्ट स्कूल की विचारधारा को स्थापित करता है जो महिलाओं और प्रकृति के बीच की कड़ी की व्याख्या करने की कोशिश करता है और प्रकृति में स्त्री सिद्धांत की कल्पना के साथ महिलाओं की जैविक भूमिका की बराबरी करता है।

हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ ब्लॉक (सिरमौर जिला) के एक सुदूर आदिवासी गाँव में, प्रत्येक आदिवासी घर में जीविका के लिए पशुधन है और आदिवासी महिलाएँ अपने स्वदेशी जातीय ज्ञान के माध्यम से पशुओं की देखभाल करती हैं।

यह देशी ज्ञान आधारित दवा किसी पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सकों के लिए पशु के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर इस गाँव की दुर्गमता के कारण अत्यावश्यक हो जाती हैं। इस संदर्भ में, एचपी में एक एनजीओ, रूरल सेंटर फॉर ह्यूमन इंट्रेस्ट्स (आरयूसीएचआई), डांगर राय कार्यक्रम के विचार के साथ आया था।

एनजीओ ने 20 महिला पशु चिकित्सकों (डेंजर डाइस) को बुनियादी चिकित्सा किट से लैस करके और उन्हें आम मवेशियों की बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षित किया। आरयूसीएचआई द्वारा मासिक आधार पर मेडिकल किट की भरपाई की गई और आदिवासियों को अब दूर के सरकारी चिकित्सालय से अपने पशुओं के लिए नियमित चिकित्सा की तलाश नहीं करनी पड़ी।

हालाँकि कई आदिवासी शुरू में महिला पैरा वेट्स के विचार के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने अंततः डॉस की विशेषज्ञता को स्वीकार किया और उनके बाद चिकित्सा सलाह और रेफरल की मांग की। अब, वर्षों से, आदिवासियों द्वारा स्वयं अनौपचारिक रूप से डांगर दाई कार्यक्रम को निरंतर बनाए रखा गया है।

(Source: www.ruchi.org.in)

निष्कर्ष

समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की अवधारणा नई नहीं है। अधिकांश आदिवासी और ग्रामीण समुदाय अपने पारंपरिक और स्वदेशी जानकारों के माध्यम से सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास के साथ अनजाने में इसका अनुसरण कर रहे हैं। समकालीन समय में, आधुनिक सीएसओ-आधारित सीबीएनआरएम गतिविधियाँ एनआरएम की प्रासंगिकता को उन स्थितियों के मनोरंजन के माध्यम से पुनः स्थापित करती हैं, जिनके तहत आदिवासी समुदाय अपने संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं।

इन मामलों के अध्ययन से निकलने वाले विषय चैंबर की अवधारणा 'किसान पहले' पर फिर से दोहराते हैं, जिसमें स्थानीय समुदायों के स्वर और स्वदेशी ज्ञान के हाशिए पर जोर दिया गया है। इन मामला अध्ययनों ने अंततः यह बताया कि आदिवासी समुदायों में नागरिक-संचालित समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, अंतरदेशीय स्वदेशी ज्ञान के हस्तांतरण की ओर जाता है और पेसा क्षेत्रों में स्थायी सकारात्मक सामाजिक आर्थिक परिणाम प्राप्त करता है।

डॉ. रुबीना नुसरत,
सहेयक प्रोफेसर,
समता और सामाजिक विकास केंद्र,
एनआईआरडीपीआर
कवर पेज डिजाइन: **वी.जी. भट्ट**

एनआईआरडीपीआर ने मनाया संविधान दिवस, व्याख्यान और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया

डॉ. के. मुरली, सहायक प्रोफेसर , एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने संविधान दिवस समारोह में व्याख्यान दिया

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद ने 26 नवंबर, 2020 को संविधान दिवस मनाया। डॉ. के. मुरली, सहायक प्रोफेसर, एनएएलएसएआर विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। भारतीय संविधान के 'संवैधानिक मूल्यों और मौलिक सिद्धांतों' पर व्याख्यान दिया ।

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसे विकास ऑडिटोरियम में एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों ने लाइव देखा और शपथ ली । श्रीमती. राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने सभी का स्वागत किया और भारत के संविधान के महत्व के बारे में बताया। डॉ. कर्णम मुरली ने भारत के संविधान के विकास, उपलब्धि, भूमिका और महत्व पर व्याख्यान दिया। इसके बाद अतिथि वक्ता द्वारा प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। प्रत्येक टीम में तीन सदस्य सहित कुल मिलाकर पाँच टीमों ने भारत के संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी में भाग लिया।

डॉ. अंजन के. भांजा, डॉ. एम. श्रीकांत और डॉ. एम. वी. रविबाबू की पहली विजेता टीम को नकद पुरस्कार रू. 3000 से सम्मानित किया गया और दूसरी विजेता टीम जिसमें श्रीमती ए. हेमलता, सुश्री हेमांगी शर्मा और श्री पी. अरविंद को रु. 2,000 के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। । बाद में, अतिथि वक्ता को सम्मानित किया गया और सत्र का समापन रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन) लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

अन्य उपस्थित लोगों में श्री शशि भूषण, निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और एफए, केंद्र प्रमुख, संकाय, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी और छात्र शामिल थे।

-सीडीसी पहल

श्रीमती. राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, उद्घाटन भाषण देते हुए

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता प्रगति पर

एनआईआरडीपीआर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह

श्रीमती. राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, में आयोजित राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान दीप प्रज्वलित करते हुए। इसके अलावा (बाएं से दाएं) डॉ. वाई. रमना रेड्डी, निदेशक, एनआरएलएम सेल, डॉ. के. जया कृष्णा, आयुर्वेद चिकित्थक, लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन), डॉ. विजया गणेश्वर रेड्डी, प्रोफेसर, डॉ. बीआरके आर सरकार आयुर्वेद कॉलेज और केसी बेहरा, पीआरओ उपस्थित थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), राजेंद्रनगर, हैदराबाद ने 13 नवंबर, 2020 को आयुर्वेद के भगवान धनवंतरि के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया।

डॉ. डी. विजया गणेश्वर रेड्डी, प्रोफेसर, डॉ. बीआरकेआर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, हैदराबाद और डॉ. के. जया कृष्णा, आयुर्वेद फिजिशियन और काउपथी प्रैक्टिशनर, सिकंदराबाद को "आयुर्वेद द्वारा जीवन शैली प्रबंधन "तथा "कोविड-19 नियंत्रण और आजीविका में आयुर्वेद की भूमिका" पर व्याख्यान देने के लिए अतिथि वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया था। । '

कार्यक्रम की शुरुआत एनआरएलएम सेल के निदेशक डॉ. वाई रमना रेड्डी के स्वागत भाषण से हुई, इसके बाद श्रीमती द्वारा राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने उद्घाटन भाषण दिया गया। अपने उद्घाटन संबोधन के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि जीवनशैली में बदलाव से दिन-प्रतिदिन के जीवनशैली संबंधी विकार हो रहे है। उन्होंने आयुर्वेद के महत्व पर बात की और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की तुलना की। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध की उपेक्षा की जाती है।

डॉ. विजया गणेश्वर रेड्डी ने दैनिक जीवन में आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डाला, आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार दिन की शुरुआत और अंत कैसे करें, क्या करें और क्या नहीं, विभिन्न मौसम के दौरान आहार और जीवन शैली कैसे बदलें, व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम का महत्व आदि ।

डॉ. के. जया कृष्ण, आयुर्वेद चिकित्सक ने भारत में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में मदद करने के बारे में श्रोताओं को बताया कि विश्व स्तर पर आयुर्वेद का भविष्य और औषधीय पौधों और उनका प्रसंस्करण,कोल्ड प्रेस्ड आयल एवं घी बनाने से आजीविका कैसे चलाई जा सकती है और ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका के साधन के रूप में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वास्थ्य में उनका महत्व क्या है । अतिथि व्याख्यान के अंत में एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया।

एनआरएलएम सेल के मिशन मैनेजर श्री टी. रविंदर राव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया । कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन) और श्री शशि भूषण, निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और वित्तीय सलाहकार, केंद्र प्रमुख, संकाय, स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी और एनआईआरडीडी के छात्र और छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम डीएवाईएनआरएलएम सेल, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा आयोजित किया गया था।

डॉ. के. जया कृष्णा, आयुर्वेद चिकित्सक (बाएं) और डॉ. डी. विजया गणेश्वर रेड्डी, प्रोफेसर, डॉ. बी. के. आर. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, हैदराबाद राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान व्याख्यान देते हुए ।

हैंडवाशिंग और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार एसबीसीसी पैकेज पर जिला और मंडल स्तर के लाइन विभागों की वर्चुअल ट्रेनिंग

स्लाइड प्रस्तुतीकरण

ग्लोबल हैंडवाशिंग डे हर 15 अक्टूबर को साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सभी महत्वपूर्ण समय पर साबुन और पानी से हाथ धोना बीमारी को रोकने और कीटाणुओं को फैलने से रोकने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। वर्तमान में, दुनिया की 40 फीसदी आबादी के पास बुनियादी हैंडवाशिंग सुविधा नहीं है। सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने के लिए यह दिन साबुन से हैंडवाशिंग की पहुंच बढ़ाने और अभ्यास करने की कार्रवाई के बारे में है।

इस साल के अभियान ने "सभी के लिए हस्त स्वच्छता' का संदेश दिया। वैश्विक हैंडवाशिंग दिवस अभियान को मनाने में राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए, समुदायों में हैंडवाशिंग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड ऑफिस (एचएफओ) की संचार संसाधन इकाई ने एक व्यापक एसबीसीसी योजना और पैकेज विकसित किया जिसमें पोस्टर, हैंडआउट, फ्लायर्स सिनेमा स्लाइड, ऑटो और बस पैनल और ऑडियो संदेश, आदि शामिल हैं ये जिला प्रशासन के साथ साझा किए गए थे और उन्हें क्षेत्र में लागू किया गया था। एसबीसीसी मीडिया प्लान को जारी रखने के लिए, यूनिसेफ एचएफओ के सहयोग से सीआरयू-एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज, स्वच्छ भारत मिशन, महिला विकास बाल कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवा विकास जयशंकर भूपालपल्ली जिले, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में जैसे लाइन विभागों से जिला और मंडल स्तर के हितधारकों के लिए जीएचडब्ल्युडी एसबीसीसी पैकेज पर एक दिवसीय वर्चुअल ओरिएंटेशन कार्यशालाओं का आयोजन 4 नवंबर, 2020 और कर्नाटक के रायचूर जिले में 10 नवंबर, 2020 को हैंडवाशिंग पैकेज के उपयोग और योजना तैयार करने के लिए किया गया।

इस प्रशिक्षण में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) भी शामिल हैं, जो माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हैंडवाशिंग के अभियान की सराहना करता हैं।

इस वर्चुअल प्रशिक्षण ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हैंडवाशिंग स्थिति के विषयों, हैंडवाशिंग - नया सामान्य, हैंडवाशिंग के लिए एसबीसीसी: उद्देश्य, रूपरेखा, योजना और पैकेज, कोविड-10 उपयुक्त व्यवहार, एसबीसीसी योजनाओं के कार्यान्वयन में लाइन विभागों की भूमिका को कवर किया।

संचार संसाधन इकाई के एसबीसीसी समन्वयक श्री श्रीनिवास ने प्रतिभागियों और वक्ताओं का स्वागत किया और इस प्रशिक्षण के आयोजन के संदर्भ और उद्देश्य के बारे में बताया।

सुश्री सीमा कुमार, यूनिसेफ एचएफओ के सी 4 डी विशेषज्ञ ने भोजन से पहले हाथ धोने की आदत पर जोर दिया, जिसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि आंकड़े इस अभ्यास में गिरावट दर्शाते हैं। उन्होंने महामारी के दौरान क्षेत्र में हैंडवाशिंग को लागू करने की निरंतर एसबीसीसी योजना पर भी जोर दिया। डॉ. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर और सीआरयू के प्रमुख ने एसबीएम पर सबसे अधिक संप्रेषित संदेश और इन संदेशों के भाग के रूप में शौच के बाद हैंडवाश पर प्रकाश डाला। उन्होंने सामाजिक विकास के लिए इन सभी व्यवहारों का अभ्यास करने पर भी महत्व दिया।

डॉ. हरि जवाहरलाल, आईएएस, जिला कलेक्टर, विजयनगरम और श्री अब्दुल अज़ीम, आईएएस, जिला कलेक्टर, जयशंकर भूपालपल्ली प्रशिक्षण सत्र में शामिल हुए और औपचारिक रूप से एसबीसीसी पैकेज का उद्घाटन किया। उन्होंने इस एसबीसीसी पैकेज की आवश्यकता ,मीडिया प्लान और हैंडवाशिंग के संदेश पर जोर दिया।

डॉ. हरि जवाहरलाल एसबीसीसी योजना से प्रभावित थे और उन्होंने इस क्षेत्र में पैकेज को लागू करने के लिए रुचि दिखाई।

उन्होंने जिला प्रशासन के सराहनीय और प्रेरक प्रतिक्रिया को साझा किया, जिसमें जिले में कोविड-19 को फैलने से रोकना शामिल था। इस पर जोर देते हुए कि रोकथाम ,इलाज से बेहतर है, उन्होंने कहा कि हितधारकों द्वारा बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए गहन निवारक उपाय करने के लिए सही समय है । इसके अलावा, डॉ. हरि ने

नीति निर्माताओं के साथ काम करने के महत्व पर भी जोर दिया, ताकि महामारी को कम किया जा सके।

श्री अब्दुल अज़ीम, आईएएस, जिला कलेक्टर, जयशंकर भूपालपल्ली ने तेलंगाना एसबीसीसी योजना का उद्घाटन किया और खान में काम कर रहे कई प्रवासियों की उपस्थिति के बावजूद कोविड -19 के प्रसार को नियंत्रित करने में जिलों के प्रयासों को साझा किया। उन्होंने मास्क, हैंडवाश, सोशल डिस्टेंसिंग और आईईसी-इन को बढ़ावा देने वाले चार नियमों पर जोर दिया। उन्होंने योजना की सराहना की और नोट किया कि पैकेज की कुछ सामग्री का उपयोग पहले ही जिलों में किया जा चुका है।

रायचूर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामकृष्ण ने जिले भर में पैकेज का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की। श्री श्रीनिवास, एसबीसीसी समन्वयक, सीआरयू-एनआईआरडीपीआर ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हैंडवाशिंग स्थिति पर एनएसएसओ और हैंडवाशिंग क्विज़ से डेटा प्रस्तुत किया। उन्होंने कोविड-19के पूर्व और पश्चात् हैंडवॉशिंग आदत पर भी प्रकाश डाला।

श्री कुलंदाई राज,C4D परामर्शदाता ,WASH एवं D R R , यूनिसेफ ने हैंडवाशिंग – न्यू नार्मल, ऑनलाइन पोल गतिविधि प्रस्तुत की, जब साबुन से हैंडवॉश करना आवश्यक है और हर समय साबुन से हाथ धोने की आवश्यकता बताई।

श्री कुलंदाई राज ने हैंडवाशिंग - उद्देश्यों, ढांचे के लिए एसबीसीसी योजना पर भी बात की और संपूर्ण एसबीसीसी पैकेज और क्षेत्र में इसके उपयोग को प्रस्तुत किया। उन्होंने अभियान की अन्य गतिविधियों पर जोर दिया जो कि हैंडवाशिंग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए आरम्भ कि जा सकती हैं। अंत में, कुलंदाई राज ने एसबीसीसी योजना के कार्यान्वयन में लाइन विभागों की भूमिका प्रस्तुत की।

यूनिसेफ के सी4डी सलाहकार, श्री किशोर ने उचित व्यवहार पर एक सत्र का संचालन किया और चार प्रमुख व्यवहारों जैसे कि मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी , हाथ धोना और श्वसन स्वच्छता पर प्रकाश डाला, जिसे सभी को महामारी से बचने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। यूनिसेफ के डब्ल्युएएस कंसल्टेंट श्री मणिकांत ने तीन राज्यों में ग्लोबल हैंडवाशिंग दिवस का अवलोकन प्रस्तुत किया।

प्रशिक्षण में एमपीडीओ, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक, पंचायत सचिव, स्वास्थ्य स्रोत व्यक्ति, जिला परियोजना प्रबंधक, एमपीओ, शिक्षक, क्षेत्र प्रशिक्षण अधिकारी, डीपीओ, जेडपी सीईओ आदि सहित कुल 160 प्रतिभागी शामिल हुए।

श्री श्रीनिवास और श्री कुलंदाई राज ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए प्रशिक्षण सत्र का समापन किया। उनकी इच्छा थी कि सम्मानित जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में, ग्लोबल हैंडवाशिंग दिवस 2020 पर सभी के लिए हस्त स्वच्छता के विषय से मेल खाते हुए महत्वपूर्ण समय के दौरान हैंडवाशिंग को बढ़ावा देने के लिए पैकेज का बड़े पैमाने में उपयोग किया जाए।

एनआईआरडीपीआर ने एसएयू उत्तर प्रदेश के स्रोत व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी और एनएसएपी के सामाजिक लेखा परीक्षा पर प्रशिक्षण आयोजित किया

अनुवर्ती कार्रवाई

- एटीआर - समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार
- एसएयू की प्रति के साथ राज्य के अधिकारियों को जीएस / डब्ल्युएस के एक महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले ए टी आर
- जिला प्रशासन को लेखा परीक्षा MIS में ए टी आर भी दर्ज करना चाहिए
- बाद के लेखा परीक्षा के दौरान एसए स्रोतव्यक्ति एटीआर में निर्दिष्ट कार्रवाई का सत्यापन करेंगे

पीएमएवाई-जी और एनएसएपी के सामाजिक लेखा परीक्षा पर प्रस्तुति से एक स्लाइड

सामाजिक लेखा परीक्षा केंद्र ,राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ,हैदराबाद ने वेब मंच के माध्यम से तीन बैचों में एसएयू उत्तर प्रदेश के सामाजिक लेखा परीक्षा स्रोत व्यक्तियों के लिए एनएसएपी और पीएमएवाई-जी के सामाजिक लेखा परीक्षा पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। पहला, दूसरा और तीसरा बैच क्रमशः 2 - 6 नवंबर, 2020, 16 वीं -22 नवंबर, 2020 और 23 वीं -27 नवंबर, 2020 से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सामाजिक लेखा परीक्षा संगठन द्वारा नामांकित कुल 521 प्रतिभागियों ने इन तीन बैचों में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

पीएमआर-जी और एनएसएपी के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, नवंबर, 2019 में एमओआरडी, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, सेंटर फॉर सोशल ऑडिट, एनआईआरडीपीआर दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए एसएयू को प्रशिक्षण और अनुभवपूर्ण

समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, सामाजिक लेखा परीक्षा केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने सभी राज्यों को कवर करते हुए दिसंबर 2019- फरवरी 2020 तक ट्रेनर्स (टीओटी) के पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित किए।

कोविड-19 के कारण, शेषस्रोत व्यक्तियों का क्षमता निर्माण बाधित हुआ । इसलिए, सामाजिक लेखा परीक्षा केंद्र , सामाजिक लेखा परीक्षा स्रोत व्यक्तियों के लिए एनएसएपी और पीएमएवाई-जी के सामाजिक लेखा परीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को 20 सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सत्र की अवधि 45 मिनट थी। दिन के अंत में, प्रतिभागियों को गूगल फॉर्म के माध्यम से 10 सवालों के साथ एक प्रश्नोत्तरी दी गई। अंग्रेजी और हिंदी में शिक्षण सामग्री, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) और क्विज़ प्रश्नों की ई-प्रतियां प्रदान की गईं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पहले और दूसरे बैच का उद्घाटन डॉ. श्रीनिवास सज्जा सहा प्रोफेसर , एनआईआरडीपीआर ने किया । तीसरे बैच के प्रशिक्षण का उद्घाटन श्री योगेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त) और निदेशक सोशल ऑडिट यूनिट, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। श्री योगेश कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में, विशेषकर पीएमएवाई-जी और एनएसएपी में वर्तमान परिदृश्य में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत एक गतिरोध दूर करने वाले अभ्यास के साथ हुई, जिससे प्रतिभागी खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से परिचित हो सकें। एनआईआरडीपीआर संकाय और यूपी राज्य के नोडल विभाग के विशेषज्ञों द्वारा सत्र लिया गया। पांच दिवसीय अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित विषय कवर किए गए थे:

- सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर मुद्दे - प्रतिभागियों के अनुभव
- लेखापरीक्षा की अवधारणा
- लेखापरीक्षा में हालिया घटनाक्रम
- एनएसएपी दिशानिर्देशों का परिचय
- राज्य योजनाएँ और एनएसएपी की कार्यान्वयन चुनौतियाँ
- एनएसएपी लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का परिचय
- एनएसएपी प्रोग्राम के प्रायोगिक लेखापरीक्षा के अनुभव
- पीएमएवाई-जी दिशानिर्देशों का परिचय
- पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन चुनौतियां
- पीएमएवाई-जी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का परिचय
- पीएमएवाई-जी के टीओटी के दौरान सामाजिक अंकेक्षण का अनुभव

सभी सत्र वीडियो रिकॉर्ड किए गए । ट्यूटर और प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान और सत्र के बाद और हर सुबह अनिवार्य पुनर्कथन ने कार्यक्रम को अत्यधिक सहभागी बना दिया। प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर ऑडियो / वीडियो स्ट्रीमिंग के मुद्दों का सामना करने पर चैट की सुविधा प्रदान की गई।

प्रशिक्षण सत्र पूरा होने के बाद, एक कार्यक्रम मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन के दौरान, प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम सामग्री, व्यावहारिक अभिविन्यास और पाठ्यक्रम सामग्री आदि पर अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही भविष्य में अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में इन सीखों और कौशल को लागू करने के तरीके भी दिए।

हालांकि, उन्होंने कुछ चुनौतियों को भी साझा किया जैसे कि कुछ स्थानों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रशिक्षण के दौरान उच्च डेटा का उपयोग, इत्यादि, जिन्होंने भागीदारी में अड़चनें पैदा कीं। अनौपचारिक प्रतिक्रिया सत्र के बाद, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से एक औपचारिक ऑनलाइन प्रतिक्रिया ली गई।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन डॉ. श्रीनिवास सज्जा , सहायक प्रोफेसर, डॉ. राजेश के सिन्हा, सहायक प्रोफेसर और डॉ. सी. धीरजा, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख (प्रभारी), सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने किया ।शाहम्मिद अली, अनुसंधान सहायक और श्री शशिधर, प्रशिक्षण प्रबंधक ने सहयोग दिया ।

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता मानदंड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	कुल
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	65 वर्ष और उससे अधिक के बीपीएल परिवार से संबंधित	रू. 200	रू. 400	रू. 600
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) और संजय गांधी निर्धन अन्नधन योजना	बीपीएल 18 साल और 65 और 80% विकलांगता	रू. 200	रू. 400 (राज्य प्रायोजित के तहत) एसजीएनएवाई	रू. 600
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्युपीएस)	40 साल से 65 साल के बीपीएल परिवार	रू. 200	रू. 400 (राज्य प्रायोजित के तहत) एसजीएनएवाई	रू. 600
4	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना - एनएफबीएस	बीपीएल 18 से 59 वर्ष	रू. 20000	-	रू. 20000
5	संजय गांधी निराधार अन्नधन योजना	पात्रता के नीचे 65 वर्ष की आयु * वार्षिक आय: रु. 21000 / -	-	रू. 600 (एकल लाभार्थी) और रु. 900 (दो या अधिक लाभार्थी)	रू. 600 और रू. 900
6	श्रवण बल सेवा राज्य निवृत्तिवान योजना	65 वर्ष से अधिक आयु वार्षिक आय: रु. 21000/ - और नाम बीपीएल सूची में शामिल नहीं है	-	रू. 600	रू. 600

पीएमएवाई-जी और एनएसएपी के सामाजिक लेखा परीक्षा पर प्रस्तुति से एक स्लाइड

कृषि पर पोषण मॉडल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम-बेहतर पोषण परिणामों के लिए पोषण संयोजन

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के सेवादल स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रस्तुति से एक स्लाइड

कोविड-19 महामारी को संबोधित करने के प्रयासों का समन्वय और संयोजन आवश्यक है। सफल अभियानों में हमेशा सार्थक जुड़ाव और मिथकों, गलत धारणाओं और सामाजिक मानदंडों को संबोधित करने के लिए विविध हितधारकों / भागीदारों की भागीदारी होती है जो किसी की पसंद, व्यवहार और प्रथाओं को प्रभावित करते हैं, समुदाय को वांछित व्यवहारों के लिए जुटाने की आवश्यकता होती है। राज्यों में बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए, विविध दर्शकों तक पहुंचने के लिए प्राकृतिक और मौजूदा प्लेटफार्मों को संलग्न करने और उन्हें सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

इस संदर्भ में, सीआरयू-एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड कार्यालय ने 'जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव' पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के सेवादल स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए सत्य साई सेवा ट्रस्ट के साथ भागीदारी की है। सत्य साईं सेवादल के स्वयंसेवक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए । पूरे राज्य से ये स्वयंसेवक इसके समधी सेवादल और समुदाय के बीच सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देने में एक महान भूमिका निभा सकते हैं। सेवादल की टीमें सामाजिक रूप से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी जानकारी का आदान-प्रदान करती हैं और यहां तक कि भक्तगण कोविड-19 राहत और सहायता के लिए भी उनकी ओर देखते हैं। वे प्रभावी रूप से आम जनता के लिए सामाजिक सेवा गतिविधियों के कार्यान्वयन का प्रबंधन करते हैं। कोविड -19 पर जागरूकता के लिए एसएसएसएसओ के अनुयायियों और समुदाय के सदस्यों के साथ लगातार और व्यवस्थित जुड़ाव द्वारा सेवादल सदस्यों की भूमिका का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

कोविड -19 पर इस आरसीसीई प्रशिक्षण के लिए सामग्री को धार्मिक स्थानों के अनुकूल और रूपांतरित किया गया था। कवर किए गए प्रशिक्षण सत्र कोविड प्रबंधन से, कोविड से संबंधित सामान्य प्रश्नों पर विशेषज्ञों के साथ प्रश्न और उत्तर सत्र और रोकथाम के लिए एसओपी सहित कोविड रोकथाम की दिशा में एसएसएसओ सेवादल टीमों की भूमिकाएँ आदि से संबंधित थे ।

सुश्री सीमा, यूनिसेफ एचएफओ के सी 4 डी विशेषज्ञ और सीआरयू के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. रमेश, प्रशिक्षण बैचों में शामिल हुए और अपनी टिप्पणी दी । स्रोत टीम में यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. संजीव, यूनिसेफ के डॉ. श्री कृषा, डब्लूएचओ से डॉ. हर्षित और डॉ. भवानी और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से डॉ. पुत्तराराजू और यूनिसेफ के सी 4 डी विशेषज्ञ श्री किशोर शामिल थे। संचार संसाधन इकाई से सुश्री अरविंदा और सुश्री जोन्स ने सभी बैचों में प्रशिक्षण सत्र संभाला।

प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हर सत्र के अंत में एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षित सेवादल अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के साथ डिजिटल स्पेस में कोविड-19 से संबंधित प्रमुख संदेशों के साथ जुड़ेंगे। सेवादल कोविड -19 के कारण कलंक और भेदभाव की रोकथाम को भी सुनिश्चित करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर समुदाय के सदस्यों के लिए सामाजिक समर्थन की सुविधा प्रदान करेंगे।

सतत योग्य आवास प्रौद्योगिकियों पर वास्तविक प्रशिक्षण कार्यक्रम

छत

- मैंगलोर टाइल्स का उपयोग
- चक्रवात का सामना करने के लिए लकड़ी के ढांचे के लिए सुरक्षित।
- परिपत्र योजना के पार केंद्रीय लकड़ी की बीम
- पिरामिड की छत स्थिरता प्रदान करती है।

दीवार

- दीवारों के निर्माण के लिए **स्थिर मिट्टी के ब्लॉक** का उपयोग किया जाता है।
- भूकंप प्रतिरोध के लिए प्लिंथ, सिल और लिंटेल बैंड।

बुनियाद

- **रैंडम मलबे** की चिनाई।
- भूकंप प्रतिरोध के लिए **आरसीसी प्लिंथ बैंड** प्रदान किया गया।

लकड़ी की खिड़की और दरवाजा

- एकल भारी सजावटी लकड़ी का दरवाजा।
- जलवायु के अनुसार छोटी खिड़की

चिकनी मिट्टी ब्लॉक घर के निर्माण में शामिल विभिन्न चरण

कौशल और नौकरियों के लिए नवोंमेषण और उपयुक्त प्रोद्योगिकी केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने 16 से 18 नवंबर, 2020 तक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए सतत आवास प्रौद्योगिकी पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीआईएटी और एसजे और कार्यक्रम निदेशक, ने निर्माण क्षेत्र में सतत आवास और ग्रामीण योजना और सरकारी अधिकारियों पर आईटीईसी कार्यक्रम के पूर्व छात्रों को संबोधित किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्थायी आवास प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर फिर से जोर देना था।

वास्तविक कार्यशाला के प्रतिभागी तीन दिनों के दौरान सक्रिय बातचीत के लिए विश्व के विभिन्न हिस्सों से वास्तुकारों, इंजीनियर और सरकारी आवास अधिकारी जैसे व्यवसायों से उपस्थित हुए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस तरह से तैयार किया गया था कि इस मुद्दे को समग्र रूप से समझने और उन तकनीकों को जोड़ने पर जो कई पूर्व छात्रों को प्रशिक्षित नहीं किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम ने जमीनी स्तर की प्रोद्योगिकियों से लेकर विभिन्न टाउन एंड सिटी प्लानिंग तकनीकों तक विभिन्न पैमाने पर दृष्टिकोण प्रदान किया।

डॉ. रमेश सक्थिवेल ने पहले दिन, सीआईएटी एवं एसजे के कार्यों की रूपरेखा और सतत विकास के लक्ष्य के लिए रूरल टेक्नोलॉजी पार्क द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों और कार्यों को बताया। सत्र राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र में एक प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ा और परिसर में विभिन्न मॉडलों में पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया।

प्रसिद्ध वास्तुविद सत्य प्रकाश वाराणसी, जो बेंगलुरु में पारिस्थितिकी और वास्तुकला में विशेषज्ञ हैं, ने एक सत्र लिया और क्षेत्र में अपने विशाल अनुभव को साझा किया। उन्होंने प्रतिभागियों से वर्तमान परिदृश्य में टिकाऊ इमारतों के निष्पादन में विभिन्न व्यावहारिक चिंताओं और अनुभवों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हर किसी के लिए बेहतर कल के लिए जीवन जीने के एक स्थायी तरीके को अपनाने के लिए हर किसी की आवश्यकता पर जोर दिया।

आर्किटेक्ट के साथ प्रतिभागियों द्वारा शुरू की गई चर्चा ने कई दिलचस्प सवाल और विचार उठाए।

कार्यशाला के पहले दिन पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी भवन प्रौद्योगिकियों के तकनीकी पहलुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। स्थायी प्रौद्योगिकियों को वास्तविक रूप से सीखने का अनुभव, अर्थात् रैट ट्रैप वालिंग , सीएसईबी मेकिंग और सीएसईबी आर्क बिल्डिंग कार्यशाला के दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण रहा।

चरण-दर-चरण प्रक्रिया को दिखाने वाली वीडियो को चल रही प्रक्रिया के लाइव प्रदर्शन के साथ जोड़ा गया है, जो प्रक्रिया को भौतिक रूप से अनुभव नहीं कर पाने के अंतराल को भरने में सुविधा प्रदान करती है। दूसरे दिन का समापन डॉ. रमेश सक्थिवेल के एनआईआरडीपीआर में महानिदेशक के बंगले पर एक सत्र के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने स्थायी सामग्री, प्रौद्योगिकी और डिजाइन का उपयोग करके प्राप्त विभिन्न लागत प्रभावी और ऊर्जा-कुशल पहलुओं का विश्लेषण किया। डीजी बंगले के इस मामले के अध्ययन ने प्रतिभागियों को व्यावहारिक रूप से इन तकनीकों का उपयोग करने के वास्तविक लाभों को समझने की अनुमति दी।

कार्यशाला में पिछले आईटीईसी कार्यक्रम के कुछ पूर्व छात्र थे, और सत्र ने उन तकनीकों पर काम करते हुए एक पुनश्चर्या पध्यक्रम के रूप में काम किया, जो हाल ही में आरटीपी पर शोध किए गए थे। इसमें हस्तनिर्मित फर्श की टाइलें और ठोस मिटटी पर एक सत्र शामिल था 'इसके द्वारा प्रतिभागियों को अपने देशों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया।

डॉ. अब्दुल रजाक, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा ने स्थायी पड़ोस योजना पर एक विस्तृत व्याख्यान दिया, जिसने स्थिरता में चुनौतियों को एक व्यापक दृष्टिकोण दिया, जिसे योजना स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि एक व्यक्ति सरल दिन-प्रतिदिन की पद्धतियों के साथ बड़े परिदृश्य में प्रभाव डाल सकता है। तीन दिवसीय कार्यशाला का समापन क्यू एवं ए. के विचार विमर्श सत्र के साथ हुआ, जिसमें बांग्लादेश, बोत्सवाना, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे के कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के बाद प्रतिभागियों द्वारा दिए गए फीडबैक ने कार्यक्रम द्वारा बनाए गए सकारात्मक प्रभाव को दिखाया। कुल मिलाकर, प्रतिभागियों ने प्रदर्शित कार्यशाला को महसूस किया और विभिन्न वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को समझाया, जिनका निर्माण सरल तरीके से किया जा सकता है और उन्होंने स्थायी आवास निर्माण पर अधिक कार्यशालाएँ करने की इच्छा भी व्यक्त की। इस पाठ्यक्रम का समन्वय डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीआईएटी और एसजे और बी एन मणि, प्रोजेक्ट इंजीनियर और विष्णुप्रिया आर, युवा पेशेवर (आर्किटेक्ट) द्वारा किया गया था।

सततयोग्य आवास प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाया गया एक मॉडल हाउस

एनआईआरडीपीआर ने कर्मचारियों के लिए आयोजित की हिंदी प्रबोध कक्षाएं

(बाएं से दाएं) श्री ई. रमेश, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, श्री बी. श्रीनिवास राव, सहायक रजिस्ट्रार (टी) और श्रीमती अनीता पांडे, सहायक निदेशक (रा.भा.) हिंदी प्रबोध परीक्षा के दौरान

सितंबर-नवंबर 2020 के दौरान, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध कक्षाएं आयोजित की गईं।

इन कक्षाओं का संचालन श्रीमती राधिका रस्तोगी ,उप महानिदेशक ,एनआईआरडीपीआर के अनुमोदन से किया गया था। हिंदी शिक्षण योजना के कोविड-19 दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रशासन कि सहायता से 26 नवंबर, 2020 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

श्री बी. श्रीनिवास राव, सहायक रजिस्ट्रार (टी) ने परीक्षार्थियों के सामने परीक्षा पत्र खोला। इस अवसर पर श्रीमती अनीता पांडे, सहायक निदेशक (रा.भा.), परीक्षाओं के अधीक्षक के रूप में और श्री ई. रमेश, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, परीक्षा के पर्यवेक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान की।

प्रबोध कक्षाएं संचालित करने से लेकर परीक्षा तक की पूरी प्रक्रिया, एन.आई.आर.डीपीआर के रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन) लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामाजिक लेखा परीक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामाजिक लेखा परीक्षा पर द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला में आयोजित प्रस्तुति से एक स्लाइड

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 26 नवंबर, 2020 को एसएयू निदेशकों और वरिष्ठ कार्यान्वयन अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामाजिक लेखा परीक्षा पर पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी 13 और 14 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला के बाद 2020 के दौरान पाँच क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन वे कोविड प्रतिबंधों के कारण नहीं हो सकीं। तदनुसार, यह कार्यशाला आयोजित की गई थी।

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार एमओआरडी ने स्वागत भाषण दिया, जिसके दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर बढ़ते खर्च और सुशासन एवं जवाबदेही ढांचे में योगदान के संदर्भ में सामाजिक लेखा परीक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

श्री संजीव कुमार ने आगे सामाजिक लेखा परीक्षा केंद्र ,राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा तैयार किए गए सामाजिक लेखा परीक्षा सूचकांक पुस्तक के बारे में उल्लेख किया है, जिसका उपयोग एसएयू द्वारा स्व-मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। उन्होंने एमओआरडी के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा से अनुरोध किया कि वे सामाजिक लेखा परीक्षा मूल्यांकन सूचकांक वाली ई-पुस्तक का विमोचन करें।

सचिव ने सामाजिक मूल्यांकन सूचकांक जारी किया और राज्यों से एक ईमानदार आत्म स्व - मूल्यांकन करने और कमियों को दूर करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने का अनुरोध किया।

राज्यों (28 एसएयू में से 23) को सामाजिक लेखा परीक्षा पर की गई प्रगति को प्रस्तुत करने, सर्वोत्तम पद्धतियों को उजागर करने और शेष प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए समयसीमा तय करने का अवसर मिला।

श्री नागेंद्रनाथ सिन्हा, सचिव, एमओआरडी, श्री संजीव कुमार, एएसएंडएफए और श्री रोहित कुमार, संयुक्त सचिव-आरई ने राज्यों को सामाजिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने के लिए बहुमूल्य प्रतिक्रिया दी।

राज्य सरकारों, योजना कार्यान्वयन अधिकारियों, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों, एनआईआरडीपीआर और मंत्रालय सहित विभिन्न हितधारकों के लिए मुख्य कार्य बिंदुओं की पहचान की गई थी। कार्यशाला में सचिवों, कार्यान्वयन अधिकारियों और एसएयू के निदेशकों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

श्रीमती अल्का उपाध्याय, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा
एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका